[श्री पी. चिदम्बरम]

है, श्री मल्होत्रा की याददाश्त उन्हें धोखा दे रही हो। मैं समझता हूं, शायद, वह बहुत व्यस्त चुनाव अभियान से पस्त हो गए होंगे। परन्तु मैं समझता हूं कि उनका यह कथन सही नहीं है। हम उन तीन आतंकवादियों को छोड़ने में सही और गलत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं परन्तु इसको एक सर्वदलीय बैठक और सर्वसम्मति से जोड़ने को मेरे विचार से स्पष्ट किया जाना चाहिए। जहां तक उन घटनाओं के बारे में समकालीन लेखों से मैंने समझा है, मुझे लगता है ऐसी कोई बात नहीं हुई थी।

महोदय, अन्त में मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे माननीय सदस्यों ने सुरक्षा बलों के कार्य की प्रशंसा की है। पुलिसकर्मी भी उसी मातृभूमि से आते हैं जहां से आप और मैं आता हूं। उनकी अपनी विफलताएं हैं। जैसे हम में से हर किसी की कोई न कोई कमजोरी है, पुलिसकर्मियों की भी कमजोरियां हैं। परन्तु अन्ततोगत्वा, मैं हम सबको यह याद दिलाना चाहता हूं कि पुलिसकर्मी, प्राय: काम के अधिक बोझ से लदा एक पुलिसकर्मी, जो एक दिन में 12 से 18 घंटे तक कार्य करता हैं, एक पुलिसकर्मी जिसका रहन-सहन बहुत ही खराब स्थिति में होता है, एक पुलिस कर्मी जो यदा-कदा विचलित भी होता है, यह वही पुलिस कर्मी होता है जो अन्य अनेक भारतीयों का जीवन बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार रहता है। एम.सी. शर्मा ऐसे ही एक पुलिसकर्मी थे। हेमन्त करकरे ऐसे ही पुलिसकर्मी थे। मुझे तब गहरा सदमा लगा जब एम.सी. शर्मा की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया गया। मुझे तब भी वैसा ही सदमा लगा जब श्री हेमन्त करकरे की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया गया। वास्तव में, हेमन्त करकरे के गुण उनकी मृत्यु के बाद ही खुलकर सामने आए हैं। परन्तु मुम्बई में कोई भी आपको बता देगा कि वह एक इंजीनियरी स्नातक, आईआईएम स्नातक और एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे। जो कुछ मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जो कुछ महीने मैं इस मंत्रालय की अध्यक्षता करूंगा, मुझे पुलिसकार्मियों के साथ काम करना पड़ेगा। मुझे उन्हें और बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। मुझे उन्हें इसलिए भी प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि वे अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करें। परन्तु इस अवधि के दौरान, सभा के सभी पक्षों से मेरी यह अपील है कि, एक पुलिसकर्मी ने यत्र-तत्र जो भी कमियां की हो, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि यह पुलिसकर्मी ही है जो आतंकवदियों के जबड़ों से हमें बचाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है।

ताज होटल में सांसद भी थे। दो पुलिस कर्मी, राहुल शिंदे और मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ताज होटल की कार्रवाई में मारे गए। मुम्बई के अन्य भागों में अनेक लोग मारे गए। इसलिए, मैं सोचता हूं कि, हमें पुलिसकर्मियों की सेवा शर्तों को बेहतर बनाने, उन्हे बेहतर उपकरण देने, उन्हें बेहतर वाहन देने, उन्हें बेहतर साजो-सामान देने का कर्तव्य निभाना हैं, हमें उन्हें उच्च सम्मान भी देना चाहिए। यह सम्मान ही है जो पुलिस बल के मनोबल को ऊपर उठाएगा और यही पुलिस बल तब भारत की एकता, सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ; मैं एक बार फिर माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। अब, मैं आपसे माननीय प्रधानमंत्री को वक्तव्य देने हेतु बुलाने का अनुरोध करता हूं।

प्रधान मंत्री (डा. मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, हाल के कुछ महीनों में आतंकवाद की घटनाओं में हो रही वृद्धि से मैं चिंतित हूं, और इन नृशंस कृत्यों के कारण हमारे सैकड़ों नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है।

मैं इस तथ्य से अवगत हूं कि आतंकवाद से निपटने में हमारे तंत्र और प्रक्रियाओं की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। सरकार की ओर से मैं अपनी जनता से माफी चाहता हूं कि इस प्रकार की नृशंस कार्रवाई को हम रोक नहीं पाए।

जहां तक मुम्बई का संबंध है यह अत्यन्त सुनियोजित तथा चालाकी से किया गया हमला था जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर आतंक फैलाना और भारत की छवि को नुकसान पहुंचाना था। इन हमलों के लिए जिम्मेवार शक्तियां हमारी धर्मनिरपेक्ष राज व्यवस्था को अस्थिर करना, साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा करना और हमारे देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को नुकसान पहुंचाना चाहती थी।

हममे से हर किसी ने इस भयानक घटना की निंदा की है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना तथा घायल लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट की है। हम सबने पुलिस तथा सुरक्षा बलों, जिनमें विशेष बल जैसे एन.एस.जी. तथा नौसेना के कमांडो भी शामिल हैं, के साध्य और देश भक्ति को नमन किया है। राष्ट्र उन पर गौरवान्वित है। मैं अत्यन्त दु:ख के साथ यह भी नोट करता हूं कि इस आतंकवादी नरसंहार में कई विदेशी नागरिकों को भी निशाना बनाया गया। मैंने उन देशों के राष्ट्र प्रमुखों या शासनाध्यक्षों से व्यक्तिगत रूप से बात की है और उन्हें पत्र लिखा है, जिन देशों के नागरिक इस आतंकवादी हिंसा का शिकार हुए है और उनसे इस बात के लिए क्षमा मांगी है कि इस घटना को रोका नहीं जा सका।

अध्यक्ष महोदय, हम चाहे जो भी कह लें या कर लें, जो जानें जा चुकी है उनकी भरपाई नहीं कि जा सकती है। यह सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है कि उनका बलिदान समय के साथ धूमिल

न पड़ जाए। संसद को दृढ़ प्रतिज्ञ होकर आतंकवाद को परास्त करने और इसे जड़ से खत्म करने के राष्ट्र के संकल्प को प्रबलित करना चाहिए। आतंकवाद की विपत्ति का दृढ़ संकल्प से ही सामना किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक सभी साधनोपायों को उपयोग में लाया जाएगा।

हमारी पहली प्राथमिकता भारत के लोगों में सुरक्षा की भावना पुनर्स्थापित करना है। हम उपस्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते जिसमें हमारे नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा का आतंकवादियों या अन्य उग्रवादी ताकतों द्वारा उल्लंघन किया जाए।

हमारे विचार में हमें तीन स्तरों पर कार्य करना होगा। सबसे पहले हमें आतंकवाद के उद्गम केन्द्र, जो कि पाकिस्तान में स्थित है का सख्ती से और प्रभावी रूप से मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट करना है। आतंकवाद की बुनियादी संरचना को स्थायी रूप से ध्वस्त करना होगा। यह पूरे विश्व समुदाय, जिसमें पाकिस्तान के लोग भी लोग भी शामिल है, की भलाई के लिए है।

मुम्बई पर आतंकवादी हमले के बाद कई राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों ने मुझसे बात की है। सभी ने संयम बरतने के लिए भारत की तारीफ की है। उन्होंने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि इस घटना के लिए जो जिम्मेवार है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैंने उन्हे बता दिया है कि हम केवल आश्वासनों से संतुष्ट नहीं होंगे। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की राजनीतिक इच्छा-शक्ति का रूपान्तरण ठोस और निरंतर कार्रवाई में होना चाहिए।

अब समय आ गया है जब अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद की चुनौती का ईमानदारी से मुकबला करना पड़ेगा। राष्ट्र नीति के हथियार के रूप में आतंकवाद का उपयोग अब स्वीकार्य नहीं है। आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई में कोई दोहरा मानदंड नहीं होना चाहिए। कोई भी अच्छा आतंकवादी या बुरा आतंकवादी है। कोई भी ऐसा मकसद नहीं है जो नरसंहार और निर्दोष लोगों की हत्या का औचित्य सिद्ध करता हो। हमें न केवल मुम्बई हमले के लिए जिम्मेवार लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने बल्कि यह सुनिश्चित किए जाने के लिए भी प्रभावी कदम उठाने आवश्यक हैं कि इस प्रकार की आतंकवादी घटना की पुनरावृति न हो।

मुझे खुशी है कि संयुक्त राष्ट्र ने आज लश्कर-ए-तैय्यबा के चार लोगों जिनमें हाफिज मुहम्मद सईद शामिल है और जमात-उद-दावा जैसे अन्य संगठनों जिनके पीछे से लश्कर-ए-तैय्यबा कार्य कर रहा है पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्रवाई की है। हमारा मानना है कि विश्व समुदाय द्वारा इस प्रकार की उद्देश्य पूर्ण कार्रवाई निरंतर तरीके से की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आतंक का पूरा का पूरा ढांचा ध्वस्त किया जा सके।

दूसरी बात, हमने इस प्रकार का हमला करने के लिए अपनी भूमि का उपयोग करने और इस प्रकार के भयानक कृत्यों के प्रायोजकों के विरुद्ध यथासंभव कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता की बात को विश्व के साथ पुरजोर तरीके से उठाना है, पाकिस्तान की सरकार द्वारा विश्व समुदाय को आश्वस्त किया जाना चाहिए कि मानवता के विरुद्ध हिंसक अपराध करने वाले इन अपराधियों के विरुद्ध पाकिस्तान द्वारा प्रभाकारी और निरंतर कार्रवाई की जाएगी।

हमने अब तक पूरे संयम के साथ कार्रवाई की है। परन्तु शिष्टता के मानदण्डों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को कमजोरी की निशानी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक अपराधी, आतंकवाद का आयोजक और समर्थक, चाहे उसका संबंध किसी भी धर्म अथवा स्थान से हो, को हमारी जनता के विरुद्ध ऐसे कायरतापूर्ण और भयानक कृत्यों की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। हमनें पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों को नोट किया है। परन्तु स्पष्ट रूप से और बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है और कार्रवाई औचित्यपूर्ण होनी चाहिए।

तीसरी बात, हमें एक राष्ट्र के रूप में यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए हम इन दोनों में से किसी एक दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं रह सकते। मुम्बई की घटना ने इस प्रकार के हमलों से निपटने के लिए हमारी तैयारी में खामियों को उजागर किया है। अपने देश की अखंडता और एकता के लिए इस अप्रत्याशित खतरे और चुनौती से निपटने के लिए हमें अपने आपको और प्रभावकारी ढंग से सुसज्जित होने की आवश्यकता है।

गृह मंत्री ने उठाए जा रहे अनेक कदमों के बारे में बता ही दिया है। प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में आतंकवाद की समस्या पर व्यापक ध्यान दिया गया है, और आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

हमारे समुद्रतटों को सुरक्षित रखने के लिए कठोरतम उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में पहले बताया जा चुका है, परन्तु इस संबंध में वास्तविक प्रणाली स्पष्ट रूप से मन्द और बहुत धीमी है। हम समुद्र से चुनौतियों के विरुद्ध हमारी समुद्रीय सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं। चूंकि तटवर्ती सुरक्षा के कार्य में वर्तमान में बहुत सी एजेंसियां लगी हुई हैं, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि समुद्रतट की रक्षा करने की पूरी जिम्मेदारी कोस्ट गार्ड को सौंपी जाएगी। भारतीय नौसेना इस प्रयोजनार्थ कोस्ट गार्ड के लिए जरूरत पड़ने पर आवश्यक सहायता देगी।

इस पर तत्काल अमल किया जाएगा। सभी प्रमुख पत्तनों के लिए विशेष सुरक्षा और संरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। हमारी समुद्र तट रेखा के पास में संवेदनशील प्रतिष्ठाथों की रक्षा के लिए इसी प्रकार के कदम उठाए गए हैं।

परम्परागत और गैर-परम्परागत चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमारे आकाश को सुरक्षित करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। वायु सेना और सिविल प्राधिकरणों द्वारा संयुक्त रूप से विमान की सामयिक निगरानी प्रारम्भ हो गई है। बाहरी अथवा सन्दिग्ध विमान का गैर कानूनी प्रवेश रोकने के लिए वायु रक्षा उपाय किए जा रहे हैं।

इन हमलों से यह सबक मिला है कि इस प्रकार की घटनाओं में तेजी से जबावी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हमने व्यापक संकट प्रबंधन हेतु एक तंत्र तैयार किया है। यह निर्णय ले लिया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गारद का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए और उन्हें विभिन्न थानों में तैनात किया जाना चाहिए और इन्हे प्रमुख महानगरों में अवस्थित किया जाना चाहिए। इसके साथ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि त्वरित प्रतिक्रिया इकाइयां समय नष्ट किए बिना दूसरे स्थानों पर पहुंच सके। जब तक एन.एस.जी. की संख्या में वृद्धि होती है, और नई यूनिटों को प्रशिक्षण दिया जाता है, तब तक सेना वायु सेना और नौसेना में मौजूद विशेष बलों और अन्य सिविलियन एजेंसियों का उपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक राज्य के द्वारा कमाण्डो इकाइयों का सृजन किया जाएगा।

हमने पहले ही आतंक से निपटने के लिए कानूनी तंत्र को मजबूत करने और एक राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी स्थापित करने का निर्णय ले लिया है। जैसा कि गृह मंत्रालय ने वचन दिया है, इन विधेयकों को शीघ्रातिशीघ्र सभा में लाया जाएगा।

जैसा कि इंगित किया गया है, भावी आतंकी हमलों के बारे में और अधिक सामयिक गुप्तचर सूचना उपलब्ध कराने के लिए तंत्र को पहले ही स्थापित किया जा चुका हैं। गृह मंत्रालय के स्तर पर दैनिक बैठकें आयोजित की जा रही हैं। आसूचना ब्यूरो का बहु-एजेंसी केन्द्र आतंकी खतरों से संबंधित सूचना एकत्र करने, उसकी प्रमाणिकता जांचने और उसे वितरित करने पर विशेष ध्यान दे रहा है। विभिन्न गुप्तचरों एजेंसियों के बीच सामंजस्य और समन्वय में सुधार किया जा रहा है। राज्यों से निवेदन किया गया है कि जिला स्तर पर गुप्तचर सूचना एकत्र करने में तेजी लाएं ताकि और अधिक कार्यवाही योग्य गुप्तचर सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

हालांकि हम अनेक अल्पकालिक और दीर्घ-कालिक उपाय करेंगे, उस बात पर आम सहमति है कि हमारी सुरक्षा में दीर्घकालिक मजबूती, विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर पुलिस संगठन को मजबूत करने पर ही आएगी। हम पुलिस आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस कार्य को एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत पूरा करने के लिए सभी प्रयास और समुचित उपाय करेंगे। हमें अपने सुरक्षा बलों को आधुनिक और नवीनतम उपकरण मुहैया कराने चाहिए जिससे वे आतंकवादी अपराधों में बढ़ते अति आधुनिक तकनीक के प्रयोग से निपट सके। हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल अत्याधिक चिन्ता और महत्व की बात है और यदि इसमें कोई कमियां हैं तो उन्हे ठीक किया जाएगा। देश को आज के समय और आज के युग में सुरक्षा और विकास की दोहरी चुनौतियों से निपटने के लिए एक आधुनिक और कुशल पुलिस बल की आवश्यकता है। भारत में आतंकी हमलों ने देश में साम्प्रदायिक विभाजन के बीज बोने और हमारे शासनतंत्र तथा हमारे सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करने का प्रयास किया है। हम प्रत्येक चुनौती के बाद और मजबूत होकर उभरे हैं और हम इस बार भी ऐसा ही करेंगे। मुझे संदेह नहीं है कि मुम्बई हमले भी उनके दुष्ट इरादों को असफल कर देंगे। सभी राजनैतिक दलों का यह दायित्व है कि वे साम्प्रदायिक घृणा और मतभेद के विरुद्ध एकजुट हों। हम आतंकवाद के विरुद्ध यह युद्ध तब तक लड़ कर जीतने में सफल नहीं हो सकते हैं जब तक कि हममें एकजुटता नहीं होगी।

अंत में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि विपत्ति के समय में ही एक राष्ट्र की खरी क्षमता की परख होती है हमें शांत और दृढ़ संकल्पित रहना चाहिए। आतंकवाद द्वारा उत्पन्न इस चुनौती का सामना करने के लिए हमें एक राष्ट्र और एक कौम के रूप में दृढ़ता से खड़ा होना होगा। हम अपने शत्रुओं को उचित जवाब देंगे। एक जीवन्त प्रजातंत्र और एक बहुविध समाज व्यवस्था के रूप में भारत की संकल्पना दांव पर लगी है। यह राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का समय है और मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। सच्चाई और न्याय हमारे साथ हैं और हम एक साथ मिलकर इस पर विजय प्राप्त करेंगे।

सायं 7.30 बजे

मुम्बई में पाकिस्तान के आतंकवादी तत्वों द्वारा किए गए घृणित आतंकवादी हमले की स्पष्ट निन्दा करने के बारे में संकल्प

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप संकल्प प्रस्तुत करें।

प्रधानमंत्री (डा. मनमोहन सिंह) : मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं:–

"कि यह सभा मुंबई में पाकिस्तान के आतंकवादी तत्वों द्वारा किए गए घृणित आतंकवादी हमले की स्पष्ट निन्दा करती है जिसमें सैंकड़ों निर्दोष लोग मारे गए तथा जिन मूल्यों के लिए भारत की पहचान है उनको नष्ट करने का प्रयास किया गया;

कि यह सभा यह भी नोट करती है कि यह घटना इस वर्ष के आरंभ से भारत के विभिन्न भागों में तथा काबुल स्थित भारतीय दूतावास पर हुए आतंकवादी हमलों के पश्चात् एक घृणित घटना के रूप में हुई;

कि यह सभा गंभीर चिंता के साथ इस तथ्य को भी नोट करती है कि आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तोएबा, जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1267 में सूचीबद्ध है तथा पाकिस्तान में प्रतिबंधित है, ने भारत के विरुद्ध आतंकवादी हमलों को जारी रखा है और लगातार सक्रिय है;

कि यह सभा यह भी नोट करती है कि सरकार ने यह घोषणा की है कि वह मुंबई पर हुए हमलों की परिस्थितियों तथा कारणों की समीक्षा कर रही है और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आवश्यक सुरक्षोपायों के लिए दृढ़प्रतिज्ञ है;

भारत के लोगों की ओर से, दृढ़तापूर्वक संकल्प करती है कि–

- भारत तब तक अपने प्रयासों को नहीं छोड़ेगा जब तक आतंकवादी और वे लोग जिन्होंने उन्हें प्रशिक्षण दिया है, वित्त पोषण किया है और उत्प्रेरित किया है, का पर्दाफाश नहीं होता और उन्हें दंड नहीं दिया जाता;
- भारत अपनी एकता, संप्रभुता और राष्ट्रीय अखंडता के विरुद्ध सभी नापाक इरादों का दृढ़तापूर्वक मुकाबला करेगा;
- भारत आतंकवाद की बर्बरतापूर्ण विभीषिका के विरुद्ध अपनी लड़ाई में दृढ़संकल्प रहेगा और विजयी होगा; और
- कि धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत का आदर्श कायम रहेगा।"

अध्यक्ष महोदय : अब मैं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प को सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है:

डा. मनमोहन सिंह ने सभा के समक्ष निम्नलिखित संकल्प पेश किया:–

"कि यह सभा मुंबई में पाकिस्तान के आतंकवादी तत्वों द्वारा किए गए घृणित आतंकवादी हमले की स्पष्ट निन्दा करती है जिसमें सैंकड़ों निर्दोष लोग मारे गए तथा जिन मूल्यों के लिए भारत की पहचान है उनको नष्ट करने का प्रयास किया गया;

कि यह सभा यह भी नोट करती है कि यह घटना इस वर्ष के आरंभ से भारत के विभिन्न भागों में तथा काबुल स्थित भारतीय दूतावास पर हुए आतंकवादी हमलों के पश्चात् एक घृणित घटना के रूप में हुई;

कि यह सभा गंभीर चिंता के साथ तथ्य को भी नोट करती है कि आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तोएबा, जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1267 में सूचीबद्ध है तथा पाकिस्तान में प्रतिबंधित है, ने भारत के विरुद्ध आतंकवादी हमलों को जारी रखा है और लगातार सक्रिय है;

कि यह सभा यह भी नोट करती है कि सरकार ने यह घोषणा की है कि वह मुंबई पर हुए हमलों की परिस्थितियों तथा कारणों की समीक्षा कर रही है और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आवश्यक सुरक्षोपायों के लिए दृढ़प्रतिज्ञ है;

भारत के लोगों की ओर से, दृढ़तापूर्वक संकल्प करती है कि–

- भारत तब तक अपने प्रयासों को नहीं छोड़ेगा जब तक आतंकवादी और वे लोग जिन्होंने उन्हें प्रशिक्षण दिया है वित्त पोषण किया है और उत्प्रेरित किया है, का पर्दाफाश नहीं होता और उन्हें दंड नहीं दिया जाता;
- भारत अपनी एकता, संप्रभुता और राष्ट्रीय अखडता के विरुद्ध सभी नापाक इरादों का दृढ़तापूर्वक मुकाबला करेगा.
- भारत आतंकवाद की बर्बरतापूर्ण विभीषिका के विरुद्ध अपनी लड़ाई में दृढ़संकल्प रहेगा और विजयी होगा; और
- कि धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत का आदर्श कायम रहेगा."

संकल्प स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : यह संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ है। हमें गर्व है कि हम सब आज इस खतरे से लड़ने में एकजुट हैं।

मैं सदन के सभी वर्गों द्वारा दिखाए गए प्रशंसनीय सहयोग के लिए आभारी हूं। हमें इस सदन से जुड़कर गर्व की अनुभूति होती है जिसने उत्कृष्ट नेतृत्व, एकता और चिन्ता का भाव प्रदर्शित किया है और जिसने आज अपने मूल्यों, शाश्वत मूल्यों के लिए लड़ने का संकल्प लिया और यह कभी भी आतंकवादियों को अपनी धरती पर सफल नहीं होने देगा।

सदन के सभी सदस्यों को मेरी शुभेच्छा और शुभकामनाएं। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.34 बजे

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 12 दिसम्बर, 2008/ 21 अग्रहायण, 1930 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।